Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

अप्रैल 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान 3
- एसओजी में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) का होगा गठन 3
- प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में स्थापित होंगे नवीन मेडिकल कॉलेज 3
- 'राजस्थान गौरव' सम्मान समारोह 4
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को अधिकारियों ने किये स्कॉच अवार्ड भेंट 4
- राजस्थान के किसानों के लिये 736 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान स्वीकृत 4
- प्रदेश की चार हस्तियाँ को पद्म श्री से सम्मानित 5
- ठीकरिया में हुआ क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 6
- 'राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना' के अंतर्गत लगभग 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी 6
- प्रदेश में खुलेंगे नए पुलिस कार्यालय, थाने एवं चौकियाँ 7
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विभागीय 'व्हाट्सएप चैटबॉट' की हेल्पलाइन का किया शुभारंभ 7
- महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित 8
- प्रदेश में 2 हज़ार टैक्स मित्र होंगे नियुक्त 9
- प्रदेश में 203 नये उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी 9
- प्रदेश में संरक्षित खेती के लिये मिलेगा एक हज़ार करोड़ रुपए का अनुदान 9
- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान सबसे आगे की श्रेणी में शामिल 10
- 'आपणी धरोहर-आपणो गौरव' पुस्तक का विमोचन 11
- 'ओपन हाउस स्टेकहोल्डर्स डायलॉग'का आयोजन 11
- 'पीएम श्री योजना' में राजस्थान के सर्वाधिक सरकारी स्कूलों का चयन 12
- देश के अग्रणी डिस्कॉम्स में शामिल हुआ अजमेर डिस्कॉम 13
- राजस्थान की पहली वंदे भारत रेल का शुभारंभ 14
- बजट 2023-24 की घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आरटीडीसी की बैठक आयोजित 14
- 'एनआरआई क्लब-21' के निर्माण कार्य हेतु लगभग 30 करोड़ रुपए की प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी 15
- राजस्थान में श्री गुरु नानक देव सिक्ख कल्याण बोर्ड का गठन 15
- राज्य स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार वितरण समारोह 16
- राजस्थान में विभिन्न वर्गों को किराए में मिलेगी 50 प्रतिशत तक छूट 16
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिये राजस्थान सम्मानित 17
- मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण 17
- राजस्थान परिवहन निगम का बस चालक राष्ट्रीय स्तर पर 'हीरोज ऑन द रोड' अॅवार्ड से सम्मानित 18
- विधानसभा अध्यक्ष ने 19 समितियों का किया गठन 18
- कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तर पर निकाली गई ऑनलाइन लॉटरी 20
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 'टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव'अवॉर्ड्स से किया जाएगा सम्मानित 20
- जेईसीसी में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ 21
- किसानों की उन्नति के लिये विभिन्न योजनाओं में 592 करोड़ रुपए स्वीकृत 21
- राज मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण 22
- महँगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण 22
- प्रदेश के एक लाख किसानों को तारबंदी के लिये मिलेगा अनुदान 23
- प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत 24
- जीआईटीबी 2023 24
- अलवर में बाबा चूहड़सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण 25
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड 25

The Vision

नोट :

राजस्थान

एसओजी में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) का होगा गठन

चर्चा में क्यों ?

31 मार्च, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिये सख्त कदम उठाते हुए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) का गठन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे प्रकरणों में लिप्त दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से बेरोज़गार और मेहनती अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और परीक्षाओं में गोपनीयता बनी रहेगी।
- इसके अलावा, चीटिंग से संबंधित प्रकरणों में प्रभावी जाँच कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायता मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने इस टास्क फोर्स के संचालन के लिये 39 नवीन पदों के सृजन तथा आवश्यक संसाधनों हेतु वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इन नवीन पदों में पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक-एक पद सहित अन्य विभिन्न पद शामिल हैं।
- यह टास्क फोर्स आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित होगी। इसके माध्यम से पेपर लीक के प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थियों एवं संस्थानों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पारित करा चुकी है। इसमें परीक्षार्थियों को कारावास, सार्वजनिक परीक्षाओं से डिबार तथा दोषियों की संपत्ति ध्वस्त करने जैसे कड़े प्रावधान किये गए हैं।

प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में स्थापित होंगे नवीन मेडिकल कॉलेज

चर्चा में क्यों ?

2 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद ज़िलों में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राज्य सरकार ने आधारभूत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करने हेतु ही मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है।
- प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में राजमैस के अधीन नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाएंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपए की लागत से होगा।
- इसके अलावा, इन कॉलेजों में आवश्यक उपकरण, फर्नीचर एवं पुस्तकों के लिये 75 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में स्वास्थ्य ढाँचा मज़बूत होगा। इससे विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिये दूर नहीं जाना पड़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि बजट वर्ष 2023-24 में प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा हुई थी।

The Vision

‘राजस्थान गौरव’ सम्मान समारोह

चर्चा में क्यों ?

3 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृति युवा संस्था द्वारा एक निजी होटल में आयोजित ‘राजस्थान गौरव’सम्मान समारोह में ‘राजस्थान गौरव’से विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि संस्कृति युवा संस्था द्वारा पिछले 28 वर्षों से ‘राजस्थान गौरव’सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है।
- राज्यपाल ने भारतीय सेना में कारगिल युद्ध के नायक रहे रिटायर्ड कर्नल वी.एस. बालोठिया, सीनियर आईएएस अजिताभ शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा के राजीव पचार, भारतीय इंजिनियरिंग सेवा के आशु सिंह राठौड़, भारतीय राजस्व सेवा के नितिन कुमार जैमन, सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक अचल शर्मा, दुबई के यंग एंटरप्रेन्योर अंकित जैन, शिव विलास रिसोर्ट के चेयरमैन स्व. बृजमोहन शर्मा, इंटरनेशनल वुडबॉल प्लेयर अजय सिंह, मांड गायिका बेगम बतूल, आईटी प्रोफेशनल सुदीप, व्यवसाय के क्षेत्र में प्रताप सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, फुटबाल खिलाड़ी अजय सिंह मीणा आदि प्रतिभाओं को ‘राजस्थान गौरव’सम्मान से सम्मानित किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को अधिकारियों ने किये स्कॉच अवार्ड भेंट

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली को विभागीय अधिकारियों ने प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड को, जिसमें एक गोल्ड एवं दो सिल्वर अवॉर्ड शामिल हैं, भेट किया। मंत्री टीकाराम जूली ने यह अवार्ड पुनः विभागीय अधिकारियों को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सेवाएँ सरलता से सुलभ, पारदर्शी व बाधा रहित तरीके से प्रदान करने के लिये जो नवाचार किये जा रहे हैं, उनका विभिन्न चरणों में परीक्षण उपरांत छह प्रमुख नवाचारों को अवार्ड हेतु चुना गया है।
- गौरतलब है कि स्कॉच अवॉर्ड राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अवॉर्ड है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को एक गोल्ड एवं दो सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तीन अवार्ड और तीन आर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट मिले हैं।
- इन अवॉर्ड्स के तहत पालनहार योजना में Gold अवॉर्ड, उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में Silver अवॉर्ड दिया गया है। इसके अतिरिक्त तीन योजनाओं यथा कोरोना सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा अनुप्रति योजना को Order of Merit Certification देकर सम्मानित किया गया है।
- गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और योजनाओं में नवाचार को पहचान प्रदान करने हेतु आयोजित राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच अवार्ड डिजीटल सेरेमनी में स्कॉच अवार्ड टीम द्वारा डिजीटल सर्टिफिकेट एवं साइटेशन प्रदान किया गया।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपने 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को सुगम, सरल, त्वरित,पारदर्शी बाधारहित गुणवत्तापूर्ण व सुविधाजनक तरीके से लोक सेवाएँ एवं प्रतिवर्ष लगभग 12,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधा लाभार्थियों के खाते में उपलब्ध करा रहा है। इस हेतु विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तकनीकी नवाचारों के माध्यम से योजनाओं का फायदा लाभार्थियों को पहुँचाने के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण व डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान के किसानों के लिये 736 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण देने के लिये 736 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने किसानों के लिये ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य के किसान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा जीवन स्तर बेहतर होगा।
- दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही खेत में ही आवास बनाने वाले किसानों को भी आवास ऋण पर अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।
- इसमें, एक अप्रैल 2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों को निश्चित समय पर चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 से अपने खेत पर आवास बनाने हेतु आवास ऋण लेने वाले किसानों को भी प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिये ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना तथा ब्याज अनुदान के संबंध में घोषणा की थी।

प्रदेश की चार हस्तियाँ को पद्म श्री से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार (द्वितीय संस्करण) में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की चार हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- पद्म पुरस्कार के दूसरे संस्करण में सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यापार, उद्योग, मेडिसिन साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली नामचीन हस्तियों को देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी, 2023 को इन पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी। उन विजेताओं को गत 22 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह के पहले संस्करण में पुरस्कार प्रदान किये गए थे। शेष बचे हुए पुरस्कार विजेताओं को अब राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया।
- प्रदेश के पुरस्कार प्राप्त करने वालों में ग़ज़ल गायकी और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को, सामाजिक कार्य के लिये डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्त्ता मूलचंद लोढ़ा को और सामाजिक क्षेत्र में ही उत्कृष्ट कार्य हेतु जयपुर के लक्ष्मण सिंह लापोडिया शामिल हैं।
- डूंगरपुर ज़िला के आदिवासी बहुल बांगड़ इलाके से ताल्लुक रखने वाले मूलचंद लोढ़ा आदिवासियों के उत्थान के लिये जागरण जन सेवा मंडल नामक संस्था चलाते हैं। मूलचंद लोढ़ा इस क्षेत्र के आदिवासी और पिछड़े इलाकों में चिकित्सा, शिक्षा और आदिवासियों के कल्याण के लिये पिछले 5 दशक से लगातार कार्य कर रहे हैं। इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिये उन्हें वर्ष 2023 का पद्म श्री सम्मान दिया गया है।
- ग़ज़ल गायकी के उस्ताद अहमद हुसैन तथा मोहम्मद हुसैन बंधुओं का पहला एल्बम गुलदस्ता 1980 में रिलीज हुआ था और अभी तक इनके 50 से ज्यादा एल्बम आ चुके हैं। वर्ष 2000 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
- हुसैन बंधुओं ने पूरी दुनिया में ग़ज़ल और शास्त्रीय संगीत के चैरिटी शो करके समाज सेवा में भी काफी योगदान दिया है।
- लक्ष्मण सिंह लापोडिया को भी राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह के पहले संस्करण के दौरान 22 मार्च को पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है।
- उन्होंने जयपुर ज़िले में जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। जल संरक्षण के लिये परंपरागत चौका पद्धति से 5 लाख वर्ग मीटर ज़मीन को सिंचित और उपजाऊ बनाया है। इलाके के करीब 100 गाँवों में जल संरक्षण के लिये उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किये हैं।

ठीकरिया में हुआ क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी के मुख्य आतिथ्य एवं राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में राज्य के बाँसवाड़ा ज़िले के ठीकरिया में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, जिसका नामकरण हरिदेव जोशी के नाम पर करने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस स्टेडियम का निर्माण मनरेगा एवं एसएफसी मद से किया गया है, जिसके रखरखाव के लिये ज़िला प्रशासन और राजस्थान क्रिकेट संघ के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।
- विदित है कि बाँसवाड़ा के कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने राज्य ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाई। इस क्रिकेट स्टेडियम के बन जाने से यहाँ की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा।
- कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये बजट में 500 करोड़ कर प्रावधान किया है तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण दे रही है।
- उल्लेखनीय है कि हरिदेव जोशी (1921-1995) राजस्थान के लोकप्रिय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता-सेनानी, पत्रकार रहे हैं। जोशी ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कई वर्ष तक पत्रकारिता के जरिये मीडिया-जगत को अपना सक्रिय योगदान दिया था। बाद में वे न केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, बल्कि असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे।

'राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना' के अंतर्गत लगभग 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

8 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु डिग्गी, फार्म पौंड एवं सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों के लिये 'राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना'के अंतर्गत लगभग 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- आगामी 2 वर्षों में फार्म पौंड निर्माण के लिये 30 हज़ार किसानों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर 50 हज़ार किया गया है। इस पर कुल 261.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

- योजना में अनुसूचित जाति-जनजाति के गैर लघु-सीमांत कृषकों को भी अब लघु-सीमांत किसानों के समान 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
- किसानों को प्रोत्साहित करने एवं संबल प्रदान करने के लिये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौंड निर्माण हेतु अनुदान सीमा को भी 90 हज़ार से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए किया गया है।
- आगामी 2 वर्षों में 40 हज़ार किसानों को 16 हज़ार किमी. सिंचाई पाइपलाइन के लिये अनुदान दिया जाएगा। इस पर वर्ष 2023-24 में 43.20 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। वहीं, 5000 डिग्गियों के निर्माण पर वर्ष 2023-24 में 158 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में सिंचाई के जल की उपलब्धता एवं सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने संबंधी घोषणाएँ की गई थीं।

प्रदेश में खुलेंगे नए पुलिस कार्यालय, थाने एवं चौकियाँ

चर्चा में क्यों ?

8 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को अधिक मज़बूत करने और इसकी आमजन तक सुगम पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में नए पुलिस कार्यालयों, थानों एवं चौकियों को खोलने की मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कार्यालयों के लिये 1369 पदों के सृजन और आवश्यक संसाधनों के लिये लगभग 201 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है।
- मुख्यमंत्री के निर्णय से वैर (भरतपुर), परबतसर (नागौर), खैरवाड़ा (उदयपुर), एडीएफ (धौलपुर) एवं लालसोट (दौसा) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे।
- इसी प्रकार अरनोद (प्रतापगढ़), तालेड़ा (बूंदी), पहाड़ी (भरतपुर), गंगाशहर (बीकानेर), रामसर (बाड़मेर), बौंली (सवाईमाधोपुर), खंडेला (सीकर), अजीतगढ़ (सीकर), सिवाना (बाडमेर) एवं आहोर (जालौर) में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे।
- वैशाली नगर (अलवर), मुक्ता प्रसाद नगर (बीकानेर), श्रीनाथ जी (राजसमंद), गोकुलपुरा (सीकर) एवं सदर पुलिस थाना बयाना (भरतपुर) में नवीन शहरी पुलिस थाने खुलेंगे। इसी प्रकार बासदयाल (अलवर), हदां (बीकानेर), राहुवास (दौसा), तनोट (जैसलमेर) एवं गोठड़ा (झुंझुनूँ) में नवीन ग्रामीण थाने खुलेंगे।
- डीडवाना (नागौर), नावाँ (नागौर) एवं कोटपूतली (जयपुर) में तीन नवीन महिला थाने खुलेंगे।
- प्रदेश की 10 पुलिस चौकी पुलिस थानों में क्रमोन्नत की गई है। इनमें अंगाई (धौलपुर), मोर (टोंक), सुलताना (झुंझुनूँ), बबाई (झुंझुनूं), जनूथर (भरतपुर), निंबी जोधा (नागौर), बडू (नागौर), डाबला (सीकर), कैलाशनगर (सिरोही) एवं जाजोद (सीकर) पुलिस चौकी क्रमोन्नत हुई है।
- प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 38 नवीन पुलिस चौकियाँ भी खोली जाएंगी। इन पुलिस कार्यालयों, थानों एवं चौकियों के सृजन से प्रदेश में कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विभागीय 'व्हाट्सएप चैटबॉट' की हेल्पलाइन का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने एम-गवर्नेंस के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विभागीय योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु 'व्हाट्सएप चैटबॉट' का वर्चुअल शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- व्हाट्सएप्प चैटबॉट के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजनाएँ, छात्रवृत्ति योजनाएँ, पालनहार, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

नोट :

- लाभार्थियों द्वारा ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक द्वारा शुल्क वहन किया जाता है लेकिन व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध लिंक पर आवेदन करने पर सुलभता एवं सहजता के साथ समय एवं राशि दोनों की बचत की जा सकती है।
- सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि विभागीय व्हाट्सएप चैटबॉट मोबाईल नंबर 9462745980 पर आवेदन करके इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती (11 अप्रैल) पर सार्वजनिक अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी तक फुले जयंती पर ऐच्छिक अवकाश दिया जा रहा था।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक ने आमजन की भावना और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
- विदित है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड टीम राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश कुमार सैनी, नागौर परबतसर से लोकेश मालाकार सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने संबंधित मांग की थी।
- उल्लेखनीय है कि महात्मा फुले ने देश से छुआछूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभायी थी। उन्होंने समाज को कुरीतियों से मुक्त कराने, बालिकाओं और दलितों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने किसानों और मजदूरों के हकों के लिये भी संगठित प्रयास किये।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा 28 जनवरी को भगवान श्री देवनारायण जयंती के ऐच्छिक अवकाश को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इससे अब राज्य में सार्वजनिक अवकाशों की संख्या 30 एवं ऐच्छिक अवकाशों की संख्या 20 हो गई है।

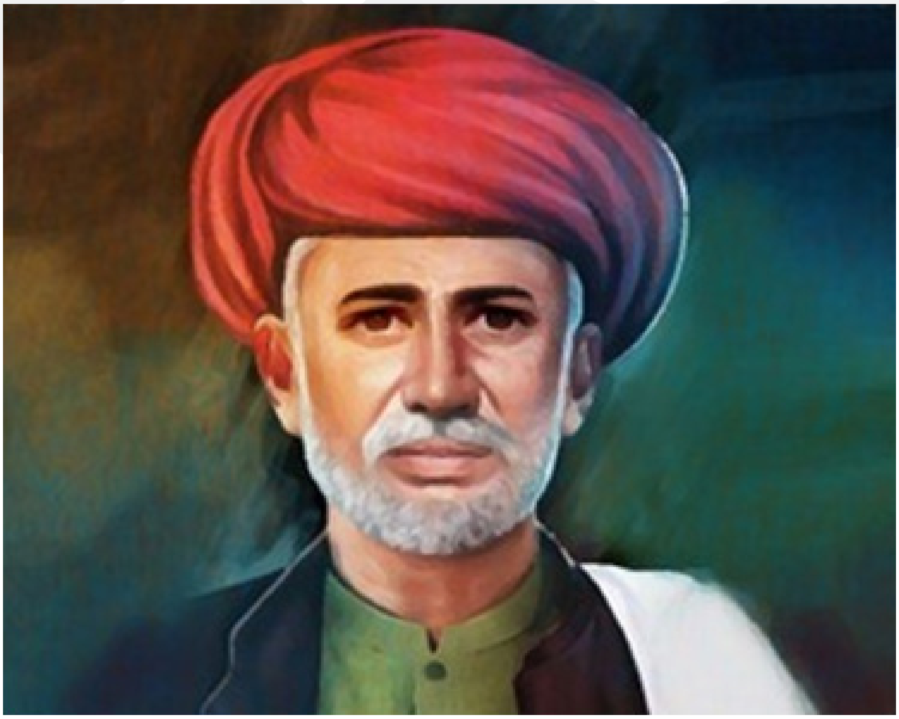

महात्मा ज्योतिबा फुले

प्रदेश में 2 हज़ार टैक्स मित्र होंगे नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियोजन की योग्यताओं तथा शुल्क निर्धारण संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आवेदन प्रक्रियाओं में आवेदकों को सहूलियत देने के लिये राज्य सरकार प्रदेश में 2 हज़ार टैक्स मित्र नियुक्त करेगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यवहारियों को सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित 'ई-टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म' विकसित करने की स्वीकृति भी दी है।
- मुख्यमंत्री की उक्त मंजूरी के बाद अब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और मूल्यवर्धित कर (वैट) जमा कराना आसान हो जाएगा।
- टैक्स मित्र के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक रखी गई है। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए सहित अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
- टैक्स मित्रों द्वारा विभिन्न टैक्स संबंधी आवेदन प्रक्रियाओं के लिये शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क का भी निर्धारण किया गया है। इसमें जीएसटी, वैट आवेदन, संशोधन, आईटीसी, ई-वे बिल, सब्सिडी आवेदन, एमएसएमई आवेदन सहित अन्य कार्यों के लिये 50 रुपए से 400 रुपए तक का शुल्क रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में जीएसटी एवं वैट आवेदन प्रक्रियाओं में सुगमता के लिये इस संबंध में घोषणा की गई थी।

प्रदेश में 203 नये उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को राजस्थान वित्त विभाग द्वारा प्रदेश में 203 नये उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। नवीन उपस्वास्थ्य केंद्रों के खोले जाने से आसपास के नागरिकों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ अपने घर के नज़दीक ही मिल सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 की क्रियान्विति में 203 नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की पदों सहित स्वीकृति जारी की गई है।
- प्रदेश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने एवं आमजन को गाँव में ही चिकित्सा एवं सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में 203 नये उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं।
- प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण कार्य हेतु 30-30 लाख रुपए स्वीकृत करने के साथ ही प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में एक-एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के 203 नये पद भी स्वीकृत किये गए हैं।

प्रदेश में संरक्षित खेती के लिये मिलेगा एक हज़ार करोड़ रुपए का अनुदान

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिये दो वर्षों में 60 हज़ार किसानों को 1 हज़ार करोड़ रुपए के अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह राशि ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिये दी जाएगी तथा इससे किसानों को संबल मिलेगा।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 हज़ार किसानों को 501 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें कृषक कल्याण कोष से 444.43 करोड़ रुपए वहन होंगे। साथ ही, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 56 करोड़ (राज्यांश 22.75 करोड़) रुपए वहन किये जाएंगे।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 30 हज़ार किसानों को 500 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इसमें अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों और समस्त लघु/सीमांत किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान सबसे आगे की श्रेणी में शामिल

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के.सिंह ने नई दिल्ली में राज्यों और राज्य उपयोगिता कंपनियों की आरपीएम (समीक्षा, योजना और निगरानी) बैठक के दौरान राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) 2021-22 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें राजस्थान चार अन्य राज्यों सहित सबसे आगे की श्रेणी (>60 अंक) में शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा-कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन (एईईई) के सहयोग से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा विकसित इस सूचकांक में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिये ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन किया गया है।
- एसईईआई 2021-22 में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप 50 संकेतकों का एक अद्यतन फ्रेमवर्क है। राज्य स्तरीय ऊर्जा दक्षता पहलों के परिणामों और प्रभावों की निगरानी के लिये इस वर्ष कार्यक्रम-विशिष्ट संकेतक शामिल किये गए हैं।
- एसईईआई 2021-22 में 5 राज्य - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना-सबसे आगे की श्रेणी (>60 अंक) में हैं, जबकि 4 राज्य - असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब – उपलब्धि प्राप्त करने वालों की श्रेणी (50-60 अंक) में हैं।
- इसके अलावा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ अपने-अपने राज्य-समूहों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पिछले सूचकांक के बाद से सबसे अधिक सुधार दर्ज किये हैं।
- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई):
  - राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई), राज्यों और भारत के ऊर्जा फुटप्रिंट के प्रबंधन तथा राज्य और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता नीतियों और कार्यक्रमों के संचालन की प्रगति की निगरानी करता है।
  - एसईईआई डेटा संग्रह में सुधार करता है, राज्यों के आपसी सहयोग को सक्षम बनाता है और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के विचारों को विकसित करता है।
  - यह राज्यों को सुधार के लिये क्षेत्रों की पहचान करने, सर्वोत्तम तौर-तरीकों से सीखने और ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन के लिये अर्थव्यवस्था अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है।
  - ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता देकर, इसका उद्देश्य कार्बनीकरण में कमी लाने के प्रयासों का संचालन करना और अधिक स्थायी भविष्य हासिल करना है।
  - सूचकांक को ऊर्जा बचत और उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़े राज्य के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी में मदद करने के लिये डिजाइन किया गया है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई):
  - यह विद्युत मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च, 2002 को की थी।
  - बीईई का मिशन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत स्व-नियमन और बाजार सिद्धांतों पर ज़ोर देने के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है।
  - ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिये, बीईई नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है और मौजूद संसाधनों और अवसंरचनाओं की पहचान करता है, उन्हें मान्यता देता है और उनका उपयोग करता है।
  - ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, विनियामक और प्रचार कार्यों के लिये कार्यादेश प्रदान करता है।

‘आपणी धरोहर-आपणो गौरव’ पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में ‘आपणी धरोहर-आपणो गौरव’पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह पुस्तक राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा प्रदेश भर में रणबाँकुरों, महापुरूषों, संत महात्माओं, लोक देवी-देवताओं और साहित्य सेवी विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बनाए जा रहे पेनोरमाओं पर केंद्रित है।
- इस अवसर पर मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने पन्नाधाय पेनोरमा, बप्पारावल पेनोरमा एवं महाराणा राजसिंह पेनोरमाओं पर बने तीन वृत्त चित्रों का भी लोकार्पण किया।
- इसके साथ ही कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के विशेष लोगो का भी विमोचन किया। इस लोगो में भक्ति, शक्ति, विरासत और साहित्य के प्रतीकों का समावेश किया गया है।
- इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉ. कल्ला ने पुस्तक की सामग्री एवं वृत्त चित्रों की गुणवत्ता की तारीफ करते हुए कहा कि इनका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, जिससे प्रदेश के नागरिक इन महान शख्सियतों के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर सके।

‘ओपन हाउस स्टेकहोल्डर्स डायलॉग’का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-कैट) में ‘ओपन हाउस स्टेकहोल्डर्स डायलॉग’कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस संवाद कार्यक्रम को राज्य के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के लिये सभी हितधारकों से इनपुट और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार और शैक्षणिक सहयोगी उद्योग के बीच सक्रिय, अंतर-निर्भर और एकीकृत सहयोग मज़बूत होगा।
- ओपन हाउस में आर-कैट के सभी मौजूदा और संभावित भागीदारों के अलावा आरटीयू सहित शैक्षणिक संस्थानों, आईटी और संबद्ध उद्योगों के प्रतिनिधियों और अन्य सभी हितधारकों की भागीदारी होने से राज्य के युवाओं को एक बेहतर तकनीकी दिशा प्राप्त हो सकेगी।
- राज्य सरकार के तकनीकी प्रोत्साहन एवं तकनीक के माध्यम से रोज़गार के साधनों को विकसित करने के लिये आर कैट निजी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के साथ काम करने को तैयार है, ताकि प्रदेश में एक बेहतर तकनीकी शिक्षा का माहौल विकसित हो सके एवं प्रदेश के युवा को बेहतर रोज़गार के लिये तैयार किया जा सके।
- वर्तमान में उद्योग जगत में तकनीक के उपयोग के कारण कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता विकसित हो रही है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आर-कैट में विभिन्न तकनीकी शिक्षा की मॉडल तैयार किये जा रहे हैं।
- इस मौके पर विविध विषयों पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। साथ ही, वर्तमान उद्योग जगत की चुनौतियों एवं शिक्षा व तकनीक के मध्य सामंजस्य जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। ‘आर-कैट आईटी साइट्स’न्यूजलेटर का भी विमोचन भी किया गया।
- राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिस्थितियों वाला राज्य है। सरकारी कार्यों में विभिन्न एप्लिकेशन के उपयोग एवं एसएसओ के उपयोग के माध्यम से राज्य ने आईटी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर न केवल प्रगति की राह को आसान बनाया है बल्कि रोज़गार के साधन भी विकसित किये हैं।
- उल्लेखनीय है कि आर-कैट Adobe, Apple, Microsoft, EC-Council, SAS, RedHat, VMWare, Oracle, CISCO, Autofina Robotics जैसी कंपनियों के साथ भागीदार है, वहीं आज फाइटेक एंबेडेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू हस्ताक्षर भी किये गए।

‘पीएम श्री योजना’ में राजस्थान के सर्वाधिक सरकारी स्कूलों का चयन

चर्चा में क्यों?

12 अप्रैल, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान ने देश में शैक्षणिक विकास के कई पैरामीटर्स में अनवरत अव्वल प्रदर्शन के गौरव के बाद अब ‘पीएम श्री योजना’ में भी सर्वाधिक सरकारी स्कूलों को चयन कराते हुए देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में राजस्थान के 21 हज़ार 356 सरकारी स्कूलों को बैंचमार्क विद्यालय माना गया है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर वैरीफाइड विद्यालयों की श्रेणी में भी राजस्थान ने देश के अन्य बड़े राज्यों को काफी अंतर से पीछे छोड़ा है।
- पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है, इनमें माध्यमिक शिक्षा के 346 और प्राथमिक शिक्षा के 56 सरकारी स्कूल शामिल हैं।
- प्रदेश के कुल 718 स्कूलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, इसमें से राजस्थान ने पहले चरण में ही 56 प्रतिशत विद्यालयों का चयन कराते हुए विशेष सफलता प्राप्त की है। जुलाई माह में द्वितीय चरण में शेष स्कूलों का चयन प्रस्तावित है।
- गौरतलब है कि पीएम श्री योजना के सरकारी स्कूलों के चयन के लिये जो बैंचमार्क निर्धारित किए गए है, उनमें एलीमेंट्री सेटअप (कक्षा 1 से 5 एवं 1 से 8 तक) तथा सैकेंडरी सेटअप (कक्षा 6 से 12 तक) में स्कूलों में नामांकन राज्य के औसत नामांकन से अधिक, अच्छी कंडीशन में विद्यालयों का पक्का भवन, बालक-बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, हाथ धोने के लिये अलग से सुविधा, सभी शिक्षकों के पास गाइडलाइन के अनुरूप आईडी कार्ड, बैरियर फ्री एक्सेस रैंप, सुरक्षा पर फोकस, विद्युत कनेक्शन, लाइब्रेरी एवं खेलकूद गतिविधियों के लिये आवश्यक सुविधाएँ जैसे पैरामीटर्स शामिल हैं।
- इनमें राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति, योजना की गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिक स्क्रूटनी (21 हज़ार 356 स्कूल), प्रथम चरण (402 स्कूल) और कुल चयन (718 स्कूल) में पूरे देश में अव्वल रही है।
- राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकन और नवाचारों के साथ-साथ छात्र-छात्राओं के लिये आवश्यक सुविधा एवं संसाधनों से परिपूर्ण स्कूल परिसर जैसे पैरामीटर्स पर यह संख्या भी पूरे देश में अव्वल थी।
- इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 3 नवंबर, 2022 को शुरू हुआ था, इस पर आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 तक स्क्रूटनी में प्रदेश के बैंचमार्क सरकारी स्कूलों (21 हज़ार 356) की ओर से आवेदन कराने में भी राजस्थान देश में अव्वल रहा।

नोट :

- ऑनलाइन आवेदन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान ने 13 हज़ार 931 सरकारी स्कूलों का सत्यापन कराते हुए देश के अन्य बड़े राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश के 7892, असम के 7776, उत्तर प्रदेश के 7054, महाराष्ट्र के 4848, कर्नाटक के 4700, पंजाब के 4632, मध्य प्रदेश के 3483, गुजरात के 2163 तथा उत्तराखंड के 1704 स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन के बाद वैरीफाइड किया गया।
- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मोहन लाल यादव ने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में चयनित प्रदेश के 402 सरकारी स्कूलों में जयपुर के सर्वाधित 28 स्कूलों का चयन किया गया है। जोधपुर के 24, उदयपुर के 22 एवं बाड़मेर के 21 सरकारी स्कूल इसमें शामिल हैं।
- इसी प्रकार अलवर एवं नागौर के 18-18, भरतपुर एवं भीलवाड़ा के 15-15, अजमेर के 14, श्रीगंगानगर, चितौड़गढ़ एवं सीकर के 13-13, झुंझुनू के 12, बाँसवाड़ा, दौसा एवं पाली के 11-11, बीकानेर, बारां, डूंगरपुर, जालौर एवं झालावाड़ के 10-10, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ के 9-9, टोंक, धौलुपर एवं राजसमंद के 8-8, चुरू, जैसलमी एवं सवाईमाधोपुर के 7-7, सिरोही के 6 एवं बूंदी के 5 विद्यालयों का चयन हुआ है।

देश के अग्रणी डिस्कॉम्स में शामिल हुआ अजमेर डिस्कॉम

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिये, जारी 11वीं पावर यूटिलिटिज इंटिग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम ने 8 स्थानों की छलांग लगा 19वाँ स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान तथा शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करने के कारण ही अजमेर डिस्कॉम का नाम देश के अग्रणी डिस्कॉम्स में शामिल हो गया है।
- इससे पहले अजमेर डिस्कॉम 27वें स्थान पर था जो 8 स्थानों की छलांग लगा 19वें स्थान पर आ गया है। राज्य के तीनों डिस्कॉम में अजमेर डिस्कॉम अग्रणी रहा है। इस रैंकिंग में जयपुर डिस्कॉम को 29वाँ तथा जोधपुर डिस्कॉम को 39वाँ स्थान मिला है।
- अजमेर डिस्कॉम ने अपने वार्षिक स्कोर को 21.5 से बढ़ाते हुए 62.1 किया है। इस वजह से अजमेर डिस्कॉम को ग्रेडिंग का भी फायदा हुआ है। अजमेर डिस्कॉम की पहले ग्रेडिंग 'सी' थी, जो अब सुधरकर 'बी'हो गई है।
- गौरतलब है कि छीजत में कमी और राजस्व सुधारों के दम पर अजमेर डिस्कॉम का नाम अब देश के टॉप डिस्कॉम में शामिल हो गया है। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देकर अजमेर डिस्कॉम ने लगभग 101 प्रतिशत राजस्व वसूली कर बिजली वितरण कंपनियों के लिये नए आयाम स्थापित किये। साथ ही अपने कई नवाचारों तथा बिजली चोरों पर कार्यवाही कर विद्युत छीजत को 10.40 प्रतिशत पर सीमित किया है।
- वर्ष 2018-19 में डिस्कॉम की हानि 2793.83 करोड़ रुपयों की थी। अजमेर डिस्कॉम की टीम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 550 करोड़ से अधिक रुपयों का लाभ अर्जित किया है।
- वहीं वर्ष 2018-19 में डिस्कॉम की छीजत 17.81 प्रतिशत थी। बिजली चोरों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर छीजत को मात्र 10.40 प्रतिशत पर ही सीमित कर दिया था।
- छीजत को कम करने के लिये अजमेर डिस्कॉम द्वारा कई नवाचार किये गए जो निर्विवाद रूप से सफल साबित हुए। इनमें मुख्य रूप से बिजली चोरी वाले संभावित क्षेत्रों में 4/6 मीटर वाले बॉक्सेज की स्थापना, सभी उपखंडों में मिनी मीटर लैब की स्थापना, सर्विस लाइन विजिबल अभियान, कॉर्डिनेट कैप्चरिंग, आदर्श जीएसएस अभियान, आदर्श फीडर अभियान, अवैध ट्रांसफार्मरों को जब्त करना, अनकवर्ड मीटर को कवर्ड करना तथा प्रत्येक उपखंड में ट्रांसफार्मर रिपेयर लैब शामिल करना मुख्य है।

दृष्टि The Vision

राजस्थान की पहली वंदे भारत रेल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर राज्य की प्रथम वंदे भारत रेल का शुभारंभ कर रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के लिये वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस ट्रेन की नियमित सेवा 13 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी तथा जयपुर, अलवर और गुड़गाँव में ठहराव-स्टेशनों के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी।
- नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इस मार्ग की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर तक के लिये 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस, इस मार्ग पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट कम समय लेगी।
- अजमेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) टेरीटरी पर दुनिया की पहली अर्ध-उच्च गति यात्री ट्रेन होगी। यह ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रेल-संपर्क में सुधार करेगी। बढ़े हुए रेल-संपर्क से क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
- यह राजस्थान की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है,जिससे जयपुर से दिल्ली के बीच यात्रा का समय कम होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेलमंत्री से आग्रह किया कि बाँसवाड़ा, टोंक, करौली आदि मुख्यालयों को भी रेलवे सुविधाओं से जोड़ा जाए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि डूंगरपुर-बाँसवाड़ा-रतलाम के बीच रेल सेवा के लिये राजस्थान सरकार और रेलवे बोर्ड के बीच एमओयू हुआ था। बाँसवाड़ा में रेल लाइन का शिलान्यास भी किया गया था। पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा एक मेजर रेल प्रोजेक्ट के लिये भूमि सहित 1250 करोड़ रुपए दिये गए थे। लेकिन जनहित का यह काम आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्त्व को देखते हुए जैसलमेर-बाड़मेर को मुंद्रा और कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिये नई रेल लाइन निर्माण की आवश्यकता है। यह नई रेल लाइन केंद्र सरकार के उपक्रम एचपीसीएल एवं राज्य सरकार के एमओयू के अनुरूप बाड़मेर में चल रहे रिफाइनरी के कार्य तथा पश्चिमी क्षेत्र के विकास की दृष्टि से काफी लाभकारी सिद्ध होगी।

बजट 2023-24 की घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आरटीडीसी की बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के जयपुर में पर्यटन भवन स्थित कार्यालय में प्रदेश के बजट 2023-24 की घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का निरंतर विस्तार करते हुए पर्यटकों को विशेष पर्यटन सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की अनुपालना में भूमि के चिह्नीकरण और डीपीआर का कार्य पूर्ण हो चुका है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनने से जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्पिटैलिटी, डेजर्ट स्टे, होटल, कैम्पिंग साइट्स, नाइट पार्क, मनोरंजन पार्क आदि सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी।
- प्रदेश में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बजट वर्ष 2023-24 घोषणा में उदयपुर, जोधपुर, अजमेर-पुष्कर, माउंट आबू एवं अलवर में बनने वाले गोल्फ कोर्स के लिये आरटीडीसी द्वारा ईओआई जारी की गई। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्ट बनने से राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिताओं के लिये डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होने के साथ ही हाई स्पेंडिंग टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी बन सकेगा।

- बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में एमआईसीई (मीटिंग, इन्सेन्टिव, कान्फ्रेंस, एक्जीबिशन) सेंटर्स की स्थापना के लिये आरटीडीसी द्वारा ईओआई जारी की गई है।
- राजस्थान प्रदेश कांफ्रेंस एवं वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है एवं एमआईसीई सेंटर्स की स्थापना से प्रदेश को इस क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।
- राज्य की पर्यटन सुविधाओं में वाटर बेस्ड पर्यटन गतिविधियों के रूप में नया अध्याय जोड़ने की मंशा से 6 स्थानों को ईको-एडवेंचर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें जयपुर का कानोता बांध, भरतपुर का बंध बारेठा बांध, जोधपुर का कायलाना व सुरपुरा बांध, पाली का हेमावास बांध, झुन्झुनु का कोट बांध शामिल हैं। इसके संबंध में भी ईओआई जारी की गई है तथा त्वरित रूप से कार्य पूर्ण करने के लिये निर्देश दिये गए हैं।
- अजमेर की फॉयसागर झील पर वाटर टूरिज्म गतिविधियाँ एवं कोटा के चंबल फ्रंट पर क्रूज संचालित करने की योजना है।
- बैठक में बजट 2023-24 घोषणा में शामिल पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी के रूप में विकास एवं पुष्कर विकास प्राधिकरण के लिये कार्ययोजना की भी विस्तृत जानकारी दी गई।

‘एनआरआई क्लब-21’ के निर्माण कार्य हेतु लगभग 30 करोड़ रुपए की प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को राजस्थान आवासन आयुक्त और ‘एनआरआई क्लब- 21’ के अध्यक्ष पवन अरोड़ा ने जयपुर में ‘एनआरआई क्लब- 21’ को क्रियाशील करने के लिये गठित कार्यकारी समिति की बैठक में बताया कि प्रदेश के प्रतिष्ठित ‘एनआरआई क्लब- 21’ के निर्माण हेतु लगभग 30 करोड़ रुपए की प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि ‘एनआरआई क्लब- 21’ की मेंबरशिप के लिये लगभग 700 लोगों ने आवेदन किया था, जिससे मंडल को लगभग 25 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
- क्लब को क्रियाशील करने, आवश्यक निर्माण एवं विकास कार्य सहित अन्य सुविधाओं को विकसित एवं सुसज्जित करने के लिये मंडल स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा आगामी दिनों में इसका तेजी से निर्माण और सुसज्जा का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
- ‘एनआरआई क्लब- 21’ जयपुर ही नहीं प्रदेश का अनूठा और अत्याधुनिक सुविधाओं से युत्त क्लब होगा जहाँ सदस्यों को गुणवत्ता युक्त समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर विकसित होने वाले इस क्लब हाउस में 25 कमरे बनाए जाएंगे, जहाँ बार, ऑल वेदर स्विमिंग पूल के साथ अन्य सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
- निजी सहभागिता के आधार पर ही यहाँ साजसज्जा, फर्नीचर्स सहित जरूरी सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।

राजस्थान में श्री गुरु नानक देव सिक्ख कल्याण बोर्ड का गठन

चर्चा में क्यों ?

14 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैशाखी पर्व के अवसर पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सिक्ख समुदाय के विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नयन एवं सर्वांगीण विकास (कल्याण) के लिये श्री गुरू नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा बोर्ड के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार द्वारा गठित गुरुनानक देव सिख कल्याण बोर्ड में कुल मनोनीत 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे। साथ ही, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। बोर्ड के सचिव पद पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उपनिदेशक स्तर का अधिकारी कार्य संपादित करेगा।

- इस बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
- इस बोर्ड का उद्देश्य सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्थान के लिये योजनाएँ प्रस्तावित करना और रोज़गार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव देना है।
- यह बोर्ड सिख समुदाय के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी सुझाव देगा। इसके साथ ही बोर्ड सिख समुदाय की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय के परंपरागत व्यवसायों को आधुनिक रूप देने के लिये भी सुझाव देगा।
- अधिसूचना के अनुसार बोर्ड सामजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक योजनाओं में सिख समुदाय की भागीदारी, समुदाय के लिये नवीन योजनाओं की प्रगति और इनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों और समाधान हेतु निरंतर समीक्षा करेगा।
- इस बोर्ड का कार्य सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों की समस्या की पहचान करना, सर्वेक्षण करना तथा उनके समग्र विकास के कार्य करना है। सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के आर्थिक अभिवृद्धि, उन्नयन, उत्थान के लिये विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करना तथा रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये उपाय सुझाना है।
- इसके साथ ही बोर्ड का कार्य सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के विकास से संबंधित योजनाओं का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को अपनी अभिशंसा के साथ प्रेषित करना, सिख समुदाय की सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने के लिये राज्य सरकार को अभिशंसा के साथ सुझाव देना, सिख समुदाय के लिये संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव देना है।
- इसके अतिरिक्त बोर्ड के प्रमुख कार्य सिख समुदाय के परंपरागत व्यवसाय की वर्तमान स्थिति, हालात में बदलाव के तौर तरीकों में आधुनिक दृष्टिकोण से उन्नयन के लिये सुझाव देना, सिख समुदाय की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना, सिख समुदाय की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं तथा ट्रस्ट में बतौर कार्मिक कार्य करने वाले ग्रंथी/सेवकों तथा कर्मचारियों को रोज़गार के बेहतर अवसर/सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से अध्ययन कर राज्य सरकार को सुझाव देना है।
- श्री गुरू नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा।

राज्य स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार वितरण समारोह

चर्चा में क्यों?

14 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 'बजट घोषणाओं को आमजन तक पहुँचाने हेतु कार्यशाला' के अंतर्गत राज्य स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न लोगों को पुरस्कार वितरण किये।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान मुख्यमंत्री ने नत्थूलाल वर्मा को अंबेडकर सेवा पुरस्कार, सुनीता छाबड़ा को अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार एवं एडवोकेट हरिलाल बैरवा को अंबेडकर न्याय पुरस्कार से सम्मानित किया।
- इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान लाने वाले प्रदेश के स्कूली बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया।
- मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित साहित्य, संविधान से संबंधित पाठ्य सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के प्रसार हेतु साहित्य, विद्यार्थियों द्वारा संचालित पुस्तकालय, संविधान के प्रावधानों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक करने हेतु नवाचारों का अवलोकन किया।
- इस अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित गीत की प्रस्तुति एवं जनहितकारी निर्णयों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

राजस्थान में विभिन्न वर्गों को किराए में मिलेगी 50 प्रतिशत तक छूट

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों को आरटीडीसी के होटल में ठहरने पर किराए में 50 प्रतिशत तक की छूट देने के आदेश जारी किये।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पिछले दिनों अधिस्वीकृत पत्रकारों सहित विभिन्न वर्गों को किराए में रियायत दिये जाने की घोषणा की थी। इस संबंध में निगम की 191 वीं बोर्ड मीटिंग में छूट देने का निर्णय लिया गया था।
- इसके अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अर्जुन अवार्ड, द्रौणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यान चंद अवार्ड एवं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति, राजकीय कार्य पर समस्त राज्य सरकारों, पीएसयू, केंद्र सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, प्रतियोगिता परीक्षा के लिये आए विद्यार्थी एवं व्यक्ति, अधिस्वीकृत पत्रकार, सर्किट हाउस के लिये पात्र अधिकारी एक अप्रैल से 31 मार्च तक 50 फीसदी रियायत के लिये पात्र होंगे।
- इसके साथ ही समस्त राज्य सरकारों, केंद्र सरकार एवं पीएसयू के कार्मिकों को 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक 50 प्रतिशत एवं 16 जुलाई से 31 मार्च तक 30 प्रतिशत रियायत देय होगी।
- इसमें दिव्यांगों को 30 प्रतिशत, महिला यात्रियों को 25 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों को 20 प्रतिशत छूट वर्ष पर्यंत दी जाएगी। राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी से जुड़े कलाकारों को प्रदर्शनी के लिये नि:शुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसी प्रकार बल्क बुकिंग कराने पर भी छूट दी जाएगी। 25 से 35 कमरे एक होटल में एक दिन बुक कराने पर एक अप्रैल से 30 सितंबर तक 30 प्रतिशत तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 36 से अधिक कमरे बुक कराने पर एक अप्रैल से 30 सितंबर तक 40 प्रतिशत तथा एक अक्टूबर से 31 मार्च तक 25 प्रतिशत छूट देय होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिये राजस्थान सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

14 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के लिये रायपुर, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में राजस्थान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिये सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अब तक 18 हज़ार 500 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वितरित किये गए हैं।
- इस योजनांतर्गत डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार भारत सरकार के कृषि सचिव द्वारा प्रदान किया गया है। साथ ही, योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में राज्य में 80 प्रतिशत फसल बीमा पॉलिसियां 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' शिविर में वितरित करवाकर उत्कृष्ट कार्य किया गया है।
- इसी प्रकार खरीफ 2022 में फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार द्वारा विकसित सी.सी.ई एग्री ऐप के माध्यम से 88 प्रतिशत ऑनलाईन किये गए हैं। इसके अतिरिक्त खरीफ 2022 तक का अधिकांश राज्यांश प्रीमियम चुकाया जा चुका है तथा योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया है। उक्त उत्कृष्ट कार्यों के दृष्टिगत राज्य को योजनांतर्गत बेहतर कार्य करने के लिये द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

17 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।

- इस सेंटर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, व्यापारिक, अकादमिक कार्यक्रमों सहित उच्च स्तरीय बैठकों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की वेबसाइट भी लॉन्च की। वेबसाइट के माध्यम से सेंटर में होने वाले बैठक, समारोह, सेमिनार आदि के लिये ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध होगी।
- मुख्यमंत्री ने सेंटर में स्थित पं. जवाहर लाल नेहरू ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। यह ई-लाइब्रेरी 1 लाख से अधिक पुस्तकों से युक्त देश-विदेश में ऑनलाईन उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने सेंटर के ब्रॉशर का भी विमोचन किया।
- इससे पहले मुख्यमंत्री ने झालाना स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों से युक्त इस सेंटर के माध्यम से आँकड़े आधारित नीतियों पर शोध तथा इनके राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन में सुगमता हो सकेगी।
- इस सेंटर में प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय हो सकेगा जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। 61 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 7 मंज़िला भवन में 160 लोगों की बैठने की क्षमता है।

राजस्थान परिवहन निगम का बस चालक राष्ट्रीय स्तर पर 'हीरोज ऑन द रोड' अॅवार्ड से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर सियाराम चौधरी को 'हीरोज ऑन द रोड' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि दुर्घटना मुक्त ड्राइवर्स को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिये राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ की तरफ से 'हीरोज ऑन द रोड' सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
- इस सम्मान के लिये देशभर से 42 ड्राइवर्स चुने गए जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही और दुर्घटना नहीं की और लगातार बस यात्रियों को उनकी मंज़िल तक सुरक्षित पहुँचाया है।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर सियाराम चौधरी पिछले 34 साल से आरएसआरटीसी में बस चालक की सेवाएँ दे रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान पूर्ण रूप से दुर्घटना मुक्त सेवाएँ प्रदान की है।
- नई दिल्ली में राजस्थान रोडवेज के मुख्य प्रबंधक पवन कटारा ने बताया कि राजस्थान पथ परिवहन निगम सुरक्षा मानकों का बखूबी से पालन करता है तथा रोड सुरक्षा के लिये राजस्थान रोडवेज हमेशा से अग्रणी रहा है, इसलिये इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवॉर्ड से राजस्थान परिवहन निगम के बस चालक सियाराम चौधरी को सम्मानित किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने 19 समितियों का किया गठन

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 19 समितियों का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने जन लेखा समिति में राजेंद्र राठौड़, प्राक्कलन समिति (क), राजेंद्र पारीक, प्राक्कलन समिति (ख), दयाराम परमार एवं गोविंद सिंह डोटासरा को राजकीय उपक्रम समिति 2023-24 का सभापति नियुक्त किया है।
- इन समितियों का कार्यकाल 31 मार्च, 2024 अथवा 15वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने तक होगा।
- जनलेखा समिति के सदस्य - राजेंद्र राठौड़ (सभापति), परसराम मोरदिया, मेवाराम जैन, गुरमीत सिंह कुनर, गोपाल लाल मीना, रोहित बौहरा, सुश्री दिव्या मदेरणा, जगदीश चंद्र, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर, ज्ञानचंद पारख, संयम लोढ़ा, महादेव सिंह हैं।

- प्राक्कलन समिति 'क'में सदस्यों के रूप में राजेंद्र पारीक (सभापति), भरोसी लाल, हरीश चंद्र मीना, पानाचंद मेघवाल, जौहरीलाल मीना, सुदर्शन सिंह रावत, बिधुरी राजेंद्र सिंह, जोगेश्वर गर्ग, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, अभिनेश महर्षि, चंद्रभान सिंह आक्या, सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजकुमार गौड़, रामकेश शामिल हैं।
- प्राक्कलन समिति 'ख'के सदस्यों में दयाराम परमार (सभापति), बाबूलाल (कठूमर), पदमाराम, श्रीमती सफिया जुबेर, दानिश अबरार, लाखन सिंह, प्रताप सिंह, नरपत सिंह राजवी, पुष्पेंद्र सिंह, सतीश पूनियाँ, बलजीत यादव शामिल हैं।
- राजकीय उपक्रम समिति के सदस्यों में गोविंद सिंह डोटासरा (सभापति), मदन प्रजापत, श्रीमती निर्मला सहरिया, रूपाराम (जैसलमेर), वीरेंदर सिंह, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विटॅल शंकर अवस्थी, रामप्रताप कासनियाँ, कांति प्रसाद, लक्ष्मण मीणा शामिल हैं।
- नियम समिति:- अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी (पदेन सभापति), श्रीमती वसुंधरा राजे, कैलाश चंद्र मेघवाल, परसराम मोरदिया, भरत सिंह कुंदनपुर, राकेश पारीक, अमीनुद्दीन कागजी, धर्मनारायण जोशी, संयम लोढ़ा।
- सदाचार समिति:- दीपेंद्र सिंह (सभापति), श्रीमती वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, संदीप शर्मा, पब्बाराम, रघु शर्मा, हरीश चौधरी।
- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति:- डॉ. राजकुमार शर्मा (सभापति), अमित चाचाण, रामलाल मीणा, पृथ्वीराज, हरेंद्र निनामा, सुभाष पूनियाँ, बिहारीलाल, बलवान पूनियाँ, सुरेश टाक, राजकुमार रोत, रफीक खान, नारायण सिंह देवल, मंजीत धर्मपाल चौधरी, अनिल कुमार शर्मा।
- विशेषाधिकारी समिति:- जे.पी. चंदेलिया (सभापति), सुश्री रीटा चौधरी, श्रीमती गंगा देवी, प्रशांत बैरवा, विजयपाल मिर्धा, वेद प्रकाश सोलंकी, संदीप कुमार, रामस्वरूप लांबा, सुमित गोदारा, आलोक बेनीवाल, श्रीमती कृष्णा पूनियाँ।
- याचिका समिति:- अर्जुन लाल जीनगर (सभापति), गिर्राज सिंह, गजराज खटाणा, मुकेश कुमार भाकर, नरेंद्र नागर, अशोक डोगरा, रामप्रसाद, ओमप्रकाश हुड़ला, दीपचंद, छगन सिंह।
- सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति:- गुरमीत सिंह कुनर (सभापति), सुरेश मोदी, इंद्राज सिंह गुर्जर, संदीप शर्मा, गोपाल लाल शर्मा, पुखराज, बाबूलाल नागर, आलोक बेनीवाल।
- पर्यावरण संबंधी समिति:- श्रीमती मंजु देवी (सभापति), किशनाराम विश्नोई, महेंद्र बिश्नोई, राकेश पारीक, गणेश घोघरा, बाबूलाल (झाडोल), हमीर सिंह भायल, खुशवीर सिंह, हाकम अली खाँ।
- पुस्तकालय समिति:- रामनारायण मीना (सभापति), रामनिवास गावडिया, गोविंद प्रसाद, सुश्री सिद्धि कुमारी, जोराराम कुमावत, धर्मनारायण जोशी, संजय शर्मा।
- महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति:- श्रीमती अनिता भदेल (सभापति), श्रीमती निर्मला सहरिया, श्रीमती मीना कँवर, श्रीमती मनीषा पंवार, श्रीमती गायत्री त्रिवेदी, श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्रीमती शोभारानी कुशवाह, श्रीमती कल्पना देवी, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।
- पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति:- जितेंद्र सिंह (सभापति), गजराज खटाणा, चेतन सिंह चौधरी, रामनिवास गावडिया, शंकर सिंह रावत, सुरेश सिंह रावत, कन्हैया लाल, मोहन राम चौधरी, जब्बर सिंह सांखला, गिरधारी लाल, नारायण बेनीवाल, जोगिंदर सिंह अवाना।
- अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति:- नगराज (सभापति), श्रीमती इंद्रा, गणेश घोघरा, रामलाल मीणा, फूल सिंह मीणा, समाराम गरासिया, कैलाश चंद्र मीणा, गोपीचंद मीणा (आसपुर), प्रताप लाल भील (गमेती), श्रीमती रमीला खडिया।
- अनुसूचित जाति कल्याण समिति:- अशोक (खंडार) (सभापति), श्रीमती गंगा देवी, अमर सिंह, हीराराम, मनोज कुमार, जगसी राम, बलवीर सिंह लूथरा, श्रीमती शोभा चौहान, श्रीमती संतोष, कालूराम, श्रीमती इंदिरा देवी।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति:- अमीन खाँ (सभापति), अमीनुद्दीन कागजी, वाजिब अली, धर्मेंद्र कुमार, रूपाराम (मकराना), गुरदीप सिंह, हाकम अली खाँ।
- प्रश्न एवं संदर्भ समिति:- विनोद कुमार (सभापति), खिलाड़ी लाल बैरवा, गिर्राज सिंह, इंद्राज सिंह गुर्जर, पूराराम चौधरी, अमृतलाल मीणा, अशोक लाहोटी, गोपाल लाल शर्मा।
- अधीनस्थ विधान संबंधी समिति:- नरेंद्र बुढ़ानिया (सभापति), वेद प्रकाश सोलंकी, किशनाराम विश्नोई, गोपी चंद मीणा (जहाजपुर), अविनाश, ललित कुमार ओस्तवाल, मंजीत धर्मपाल चौधरी, सुश्री रीटा चौधरी, सुरेश मोदी।

The Vision

कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तर पर निकाली गई ऑनलाइन लॉटरी

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2023 को प्रमुख शासन सचिव कृषि व उद्यानिकी दिनेश कुमार की अध्यक्षता में कृषि पंत भवन में कृषक उपहार योजना के तहत कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई।

प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत कोटा खंड की भवानी मंडी के कृषक प्रदीप का 2 लाख 50 हजार रुपए का प्रथम पुरस्कार, हनुमानगढ़ खंड की गोलूवाड़ा मंडी के कृषक जसवंत का 1 लाख 50 हज़ार रुपए का द्वितीय पुरस्कार और हनुमानगढ़ मंडी के कृषक मोहनलाल का 1 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार निकला।
- राज्य स्तरीय लॉटरी वर्ष में एक बार निकाली जाती है, जिसमें प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग-अध्यक्ष, प्रशासक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड-सदस्य और निदेशक कृषि विपणन विभाग-सदस्य सचिव होते हैं।
- वर्ष 2022 की राज्य स्तरीय लॉटरी राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सॉफ्टवेयर द्वारा निकाली गई।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 'टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव'अवॉड्र्स से किया जाएगा सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 'टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव'अवॉड्र्स से सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 26 अप्रैल को गुरुग्राम में होने वाले सम्मान समारोह में इस अवॉड्र्स से सम्मानित किया जाएगा।
- कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा गेस्ट ऑफ ऑनर दिल्ली रेरा के चेयरमैन आनंद कुमार होंगे।
- गौरतलब है कि आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मंडल को कुल 14 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डस, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेन्सी, नेशनल रियल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी और 'स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड' जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।

जेईसीसी में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के आयुष राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में केंद्रीय आयुष मंत्रालय, राज्य के आयुष विभाग तथा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- आयुष राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि ‘निरोगी राजस्थान’की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति को लगातार बढावा दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप आयुष पद्धति के प्रति लोगों में रूझान बढ़ा है और यह एलोपैथी के मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। अन्य राज्यों के समक्ष राज्य सरकार की यह एक अनुकरणीय पहल है।
- आयुष राज्य मंत्री ने आयुष के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान के जोधपुर में देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। कोविड के समय आयुष विभाग द्वारा विकसित काढ़ा पूरे देश-दुनिया में कारगर सिद्ध हुआ है।
- 23 अप्रैल तक आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेले में लगभग 100 स्टॉल्स के माध्यम से विभिन्न आयुष उपकरण एवं औषधियाँ प्रदर्शित की गई हैं, जिनके माध्यम से आगंतुकों को जागरूक किया जाएगा।
- आरोग्य मेले में आयुष उद्योग प्रदर्शनी, निरूशुल्क ओपीडी, दवा वितरण, उपचार एवं परामर्श के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- मेले में चार दिन में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाएगा। यह सत्र अस्वस्थ जीवन शैली के कारण उत्पन्न हो रही स्वास्थ्य समस्याओं से निजात पाने के लिये कारगर साबित होंगे।

किसानों की उन्नति के लिये विभिन्न योजनाओं में 592 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव करने में 4.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिये 10 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4500 रुपए प्रति हैक्टेयर की अनुदानित दर रखी गई है।
- वहीं 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिये प्रति परिवार 5 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए व्यय करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र, 50 हज़ार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
- कृषि स्नातक बेरोज़गार युवाओं को भी 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिये 4-4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- राज्य सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं में कृषक कल्याण कोष से 588 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4.60 करोड़ रुपए (राज्यांश) का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री की स्वीकृति से प्रदेश के लाखों कृषक एवं पशुपालक लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

The Vision

राज मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत भवन में राज मत्स्य योजना पोर्टल का ऑनलाइन लोकार्पण किया। अब राज्य में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिये आवेदन प्रक्रिया होगी पूर्णत: ऑनलाइन होगी।

प्रमुख बिंदु

- कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसान घर बैठे विभागीय योजनाओं के लिये स्वयं के एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, साथ ही आवेदन की प्रगति के बारे में भी पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले पाएंगे।
- आवेदन विभाग में प्राप्त होने से लेकर अनुदान स्वीकृति तक प्रत्येक चरण की सूचना किसान को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
- विभाग द्वारा संचालित निम्न योजनाओं का मिल सकेगा लाभ :
  - मछली पालन हेतु निजी ज़मीन पर तालाब का निर्माण,
  - मछली पालन पर प्रथम वर्ष में होने वाले उपादान पर खर्च,
  - खारे पानी में झींगा पालन हेतु तालाब का निर्माण,
  - मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना,
  - मछली पकड़ने के शिल्प एवं साजो-सामान/नाव के क्रय हेतु,
  - रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, फिश फीड इकाई, केज कल्चर हेतु अनुदान योजना,
  - आईस प्लांट/कोल्डस्टोरेज की निर्माण एवं पुनरुद्धार हेतु योजना,
  - खुदरा मछली बाज़ार एवं संसाधनों के विकास हेतु योजना,
  - मोबाइल/खुदरा रंगीन मछली विक्रय केंद्र कियोस्क की स्थापना हेतु योजना,
  - प्रशीतित ट्रक तथा इंस्यूलेटेड ट्रक के क्रय हेतु योजना,
  - मोटर साईकिल आइस बॉक्स सहित क्रय हेतु,
  - साईकल आइस बॉक्स योजना,
  - सेविंग कम रिलीफ योजना,
  - मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना,
  - प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना।

महँगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर महँगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने महँगाई राहत कैंप की दिशानिर्देश पुस्तिका का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट के माध्यम से आमजन का राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा उन्हें योजनाओं के लाभ एवं उद्देश्य के बारे में जागरूक किया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महँगाई राहत शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

- उल्लेखनीय है कि महँगाई राहत कैंप से सभी जरूरतमंद परिवारों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महँगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिये 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेशभर में महँगाई राहत कैंप आयोजित किये जाएंगे।
- कैंपों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महँगाई की मार से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री 24 अप्रैल को सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा में महँगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आयुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट पर 10 योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं पंजीकरण के लिये आवश्यक दस्तावेजों की सूची, कैंप में पंजीकरण कराने से संबंधित उपयोगी फोटो-वीडियो गैलरी तथा सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची उत्तर सहित उपलब्ध होगी।
- कैंप से संबंधित आने वाली समस्याओं के समाधान के लिये प्रत्येक ज़िले हेतु जारी हेल्पलाइन नंबर भी वेबसाइट पर मिल सकेंगे।
- इन योजनाओं का मिलेगा लाभ-
  - मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर
  - मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिज़ली योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिज़ली
  - मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिज़ली योजना में कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिज़ली
  - मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
  - मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोज़गार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोज़गार
  - इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर
  - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
  - मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
  - मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
  - मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिये प्रति पशु 40 हज़ार रुपये का बीमा कवर

प्रदेश के एक लाख किसानों को तारबंदी के लिये मिलेगा अनुदान

चर्चा में क्यों ?

22 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिये प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर के तारबंदी के हेतु 444.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों को दो वर्षों में निस्तारित करने की दृष्टि से सहमति दी है।
- उन्होंने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिये न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
- तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिये अनुदान राशि 70 प्रतिशत की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में तारबंदी पर अनुदान में करीब 444.40 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इनमंक 391 करोड़ रुपए कृषक कल्याण कोष से, 25 करोड़ रुपए राज्य योजना 'तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान' से वहन होंगे। शेष 28.40 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से (राज्यांश 11.36 करोड़ रुपए) खर्च किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तारबंदी को निरंतर जारी रखने की घोषणा की गई थी।

प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

- 24 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर ज़िले की महापुरा ग्राम पंचायत से महंगाई राहत शिविरों का शुभारंभ किया। उन्होंने शिविर में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 23 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर महंगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण एवं महंगाई राहत कैंप की दिशा-निर्देश पुस्तिका का विमोचन किया था।
- आमजन को महंगाई से राहत देने के लिये प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत की गई है। इन महंगाई राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन करवाकर आम लोग राज्य सरकार की 10 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं।
- प्रदेश के सभी ज़िलों में 30 जून तक ये महंगाई राहत शिविर आयोजित होंगे।
- इन महंगाई राहत शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (घरेलू), मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना से अधिकाधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है।

महंगाई राहत कैंप
24 अप्रैल से
फ्री राशन
500
100 यूनिट बिजली फ्री
10 लाख रु
25 लाख रु
40 हजार रु का पशु बीमा
1000
125
इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी

जीआईटीबी 2023

चर्चा में क्यों?

- 25 अप्रैल, 2023 को द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाज़ार (जीआईटीबी 2023) के 12वें संस्करण का समापन राजस्थान के सीतापुर स्थित जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में हुआ।

प्रमुख बिंदु

- तीन दिवसीय जीआईटीबी का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
- इस आयोजन में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर), इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए.) और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो) जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एसोसिएशन शामिल हुए।

- इस मेगा इवेंट में 56 देशों के करीब 283 प्रमुख इनबाउंड फॉरेन टूर ऑपरेटर्स (एफटीओ) ने विदेशी खरीदारों के रूप में भाग लिया।
- दो दिनों के दौरान करीब 11,000 बी2बी बैठकें आयोजित हुईं। मार्ट में राजस्थान सहित 9 राज्यों के राज्य पर्यटन बोर्ड शामिल हुए।
- इस अवसर पर राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो) के प्रेसिडेंट महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आने वाले बायर्स के लिये फैम टूर्स भी आयोजित किये गए हैं, जिनमें कुल 60 टूर ऑपरेटर्स शामिल होंगे। ये तीन यात्रा कार्यक्रम हैं- जयपुर-जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर; जयपुर-सरिस्का-रणथंभौर और जयपुर-उदयपुर-देवगढ़-पुष्कर।
- ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार में देश के कुछ राज्यों की ओर से लगाए गए स्टेट पवैलियन में अपनी-अपनी पर्यटन विशेषताओं की जानकारी दी गई, जिसमें राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु कुछ प्रमुख राज्य हैं।
- यहाँ राज्य की सफारी, रूरल टूरिज्म, नए होटल्स, हेरिटेज होटल्स एवं साइट्स और फेयर फेस्टिवल को प्रमोट किया गया।
- जीआईटीबी के 12 वें संस्करण में 'इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया - अनलॉकिंग द पोटेंशियल' पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई।
- फिक्की और नांगिया एंडरसन एलएलपी द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में इनबाउंड टूरिज्म के वर्तमान परिदृश्य के बारे में ध्यान आकर्षित करना है। रिपोर्ट में क्रूज टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म से लेकर गोल्फ और पोलो टूरिज्म के साथ-साथ फिल्म टूरिज्म और रूरल टूरिज्म पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।
- देश में पर्यटन के भविष्य पर प्रकाश डालते हुए, रिपोर्ट कुछ प्रमुख कदमों की भी जानकारी प्रदान करती है, जो भारतीय पर्यटन उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिये उठाए जा सकते हैं। इनमें वीजा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सुरक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करना, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, उपयुक्त पर्यटन पेशकशों को विकसित करना, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं।
- यह रिपोर्ट भारत में इनबाउंड टूरिज्म के वर्तमान परिदृश्य, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जा रही पहलों, भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए विभिन्न विशिष्ट पर्यटन उत्पादों, भारत की जी-20 पर्यटन प्राथमिकताओं और पर्यटन क्षेत्र के संबंध में विजन 2047 पर प्रकाश डालती है।

अलवर में बाबा चूहड़सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत अलवर ज़िले में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी बाबा चूहड़सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार द्वारा ज़िले में पर्यटन को बढावा देने हेतु ऐतिहासिक धरोहरों एवं धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है जिससे स्थानीय स्तर पर ही आमजन के लिये रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि बाबा चूहड़सिद्ध के स्थान पर बनी यह लवकुश वाटिका ज़िले में पर्यटन को बढाने में महत्त्वपूर्ण साबित होगी। अलवर ज़िले में पर्यटन की अपार संभावना है तथा यहाँ पर्यटन स्थलों को विकसित कराकर वहाँ रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास है।
- विदित है कि बाबा चूहड़सिद्ध मंदिर को सोलर लाइट से विद्युतीकृत कराने की घोषणा भी की गई है।
- धार्मिक पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह वाटिका बहुपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही, इससे स्थानीय स्तर पर आमजन को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। यह वाटिका आमजन के लिये स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में बेहद लाभाकारी सिद्ध होगी।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2023 को केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) ने राजस्थान आवासन मंडल को रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बंदेलकर और रेरा दिल्ली के चेयरमैन और वरिष्ठ आईएएस आनंद कुमार ने एक राष्ट्रीय स्तर के समारोह में राजस्थान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को इस सम्मान से नवाज़ा।
- राजस्थान आवासन मंडल को देश में सर्वाधिक हाउसिंग प्रोजेक्टस रेरा में रजिस्टर्ड करने, सर्वाधिक आवास विक्रय करने और रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिये इस महत्त्वपूर्ण सम्मान से नवाजा गया।
- विदित है कि मंडल को यह पुरस्कार केंद्रीय आवासन मंत्री हरदीप पुरी द्वारा दिया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के चलते वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।
- इससे पहले समारोह में 'रियल एस्टेट इन द एरा ऑफ रेरा' विषय के पैनल डिस्कशन के लिये राजस्थान आवासन आयुक्त को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसी मंच पर आवासन आयुक्त को सम्मानित भी किया गया।
- आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने इस मौके पर कहा कि आवासों में रेरा रजिस्ट्रेशन आईएसआई मार्का की तरह काम करता है। उन्होंने कहा कि रेरा आमजन और खरीददार में डेवलपर और बिल्डर के प्रति भरोसा बढ़ाता है और तय समयावधि में बेहतरीन गुणवत्ता के साथ आवास उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता लाता है।
- आवासन आयुक्त ने कहा कि 101 प्रोजेक्ट रेरा नंबर रजिस्टर्ड करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था राजस्थान आवासन मंडल बन गया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सरकारी एजेंसियाँ रेरा रजिस्ट्रेशन से बचती हैं, लेकिन मंडल ने ग्राहकों के विश्वास की खातिर सभी प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड करवाया है।
- गौरतलब है कि आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मंडल को कुल 15 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डस, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी. और 'स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड' जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।

The Vision

नोट :